भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 323

जिसका उत्तर मंगलवार 5 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना

323. श्री बी. विनोद कुमारः

क्या भारी उद्योग और उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014-18 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और रोजगार सृजित करने में किस हद तक सफल रही है;

(ख) योजना के संबंध में सरकार को किस प्रकार के निवेश प्राप्त हुए है; और

(ग) मिशन योजना (2014-18) के कार्यान्वयन ने किस प्रकार वैश्विक व्यापार में देश को लाभ पहुंचाया है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 एक राष्ट्रीय दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और उनके विनिर्माण के लिए विजन तथा रोडमैप उपलब्ध कराता है। इस योजना को वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को समर्थ बनाने तथा किफायती और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। इस योजना में उद्योग से कुछ योगदान के साथ योजना की अवधि के दौरान लगभग ₹14,000 करोड़ के संचयी परिव्यय का अनुमान है। एनईएमएमपी 2020 के तहत, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2015 में एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना तैयार की। सरकार ने एनईएमएमपी 2020 में परिकाल्पित ₹14,000 करोड़ की सहायता के साथ 6 वर्ष की योजना के बदले ₹795 करोड़ के परिव्यय के साथ दो वर्षों के लिए एक प्रायोगिक योजना के रूप में इस योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया। इस समय, फेम-इंडिया योजना का चरण-I चल रहा है,जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक मूलतः दो वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अंतिम विस्तार तथा ₹895 करोड़ तक कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया है।

इस योजना के आरंभ होने और दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक, सरकार ने लगभग 2,65,032 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की वित्तीय सहायता (मांग प्रोत्साहन) की है। मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए फेम-इंडिया योजना के तहत 34 ओईएम के वाहनों के कुल 124 मॉडल पंजीकृत किए गए। उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न शहरों/राज्यों को 585 इलेक्ट्रिक बसें भी मंजूर की गई है।

फेम-इंडिया योजना के चरण-I में प्राप्त अनुभव के आधार पर, यह देखा गया है कि देश में चार्जिंग अवसंरचना की अनुपलब्धता और लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का न होना, संभावित परिणाम के साथ, इस योजना को सुचारु रूप से आरंभ करने के लिए मुख्य बाधाएं है। मोटर, कंट्रोलर जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अभी पूर्णतः विकसित किया जाना है।

*****